AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

विदेश नीति और रणनीतियों पर भारत की अर्थव्यवस्था का प्रभाव

Sachin Sharma
Research Scholar
University of Technology, Jaipur
Dr. Shweta Rai
Supervisor
University of Technology, Jaipur

DECLARATION: I ASAN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BYME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANYO F SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THEREASON OF CONTENT AMENDMENT/ OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, IHAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETEDECLARATION OF THE AUTHOR ATTHE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

सार

भारत के कई पर्यवेक्षक देश को खेल–बदलती क्षमताओं के साथ एक उभरती हुई महान शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। हालाँकि, देश की क्षमता के ऐसे आकलन हाल ही में हुए हैं और 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद ही सामने आए। इन सुधारों ने सरकारी नीतियों के उदारीकरण और भारतीय निजी क्षेत्र के पुनरोद्धार के माध्यम से तेज आर्थिक विकास को गति दी। भारत ने पाकिस्तान के साथ तीन युद्ध लड़े हैं और कई निकट–युद्ध स्थितियों का सामना किया है। तनाव का प्राथमिक स्रोत कश्मीर राज्य के लिए परस्पर विरोधी दावे रहे हैं। पहले दो भारत–पाकिस्तान युद्ध राज्य को लेकर लड़े गए और तीसरे में यह कार्रवाई का रंगमंच था। उत्तर में, लंबे समय से विवादित सीमा पर चीन के साथ 1962 के युद्ध में भारत की हार ने नई दिल्ली को बीजिंग के साथ अपने संबंधों के बारे में असुरक्षा की भावना दी। चीन के परमाणु परीक्षणों और पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति ने भारतीय असुरक्षा को बढ़ा दिया है। दक्षिण–पूर्व में, भारत के निकटतम संबंध वियतनाम के साथ थे, एक ऐसा तथ्य जो इस बात को रेखांकित करता है कि शेष दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध कितने पतले थे। आत्मनिर्भरता और समाजवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने और अधिक ध्यान अंदर की ओर केंद्रित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया गया; 1990 में, उदाहरण के लिए, यह केवल कुछ सौ मिलियन डॉलर था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को व्यापक रूप से शोषक और खिलाड़ियों के रूप में भारत को कमजोर करने और इसे पश्चिम पर निर्भर बनाने के लिए एक बड़े विदेशी प्रयास में माना जाता था।

कुंजीशब्दः *गाँधीवादी, प्रभाव, नीति,*

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

प्रस्तावना

राष्ट्र–राज्यों के विकास और उनके बीच बढ़ती परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप आधुनिक समय में विदेश नीति का निर्माण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया जिसने कई राज्यों को संप्रभु संस्थाओं में मुक्त कर दिया है, ने राज्यों के बीच अंतर्संबंधों को और गति प्रदान की है। प्रत्येक राज्य के लिए विदेश नीति की आवश्यकता पर विद्वानों और राजनेताओं के बीच एकमत है, क्योंकि कोई भी राज्य शेष दुनिया से पूर्ण अलगाव में कार्य करना पसंद नहीं करेगा। फेलिक्स ग्रॉस ने कहा कि किसी राज्य विशेष के साथ संबंध न रखने का निर्णय भी एक विदेश नीति है या दूसरे शब्दों में, एक निश्चित विदेश नीति का न होना भी एक विदेश नीति है। उदाहरण के लिए, 1992 तक भारत का इजरायल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रखने का निर्णय उसकी विदेश नीति का अभिन्न अंग था। भारत इजरायल के विरोधियों, यानी अरब राज्यों के साथ अच्छे राजनयिक और व्यापारिक संबंध जारी रखना चाहता था, जिनका कश्मीर पर समर्थन भारत के लिए महत्वपूर्ण था, साथ ही कच्चे तेल तक पहुंच भी।

विदेश नीति के बिना एक राज्य बिना किसी रणनीति के फुटबॉल खेलने वाली टीम की तरह दिखेगा, इसलिए सभी ग्यारह खिलाड़ी खेल के मैदान पर अपनी भूमिका और कार्यों के बारे में अनजान हैं। इस प्रकार, एक आधुनिक राज्य में जिसमें विदेश नीति का अभाव है; द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने या बहुपक्षीय मंचों में भाग लेने में विदेश मंत्रालय की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय के पास देश की सेना की सशस्त्र तैयारियों के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने दोस्तों को परिभाषित करने और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दुश्मनों को पहचानने के लिए कोई मानदंड स्थापित नहीं किया गया है। वित्त और साथ ही वाणिज्य मंत्रालय द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान आयात–निर्यात के मुद्दों पर स्टैंड लेने के लिए संघर्ष करेंगे। विदेश नीति के बिना एक राज्य की तुलना दिशाओं के ज्ञान के बिना गहरे समुद्र में एक जहाज से की जा सकती है। जैसे ही जहाज पर रडार इसे भूमि गंतव्य की ओर ले जाता है, विदेश नीति राज्य को अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने और राष्ट्र–राज्यों के बीच सही स्थान प्राप्त करने की ओर ले जाती है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि जब तक संप्रभु राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में काम करते हैं, तब तक विदेश नीति मौजूद रहेगी।

विदेश नीति की परिभाषा

विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विदेश नीति की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पता चलता है। विदेश नीति की परिभाषा पर विद्वानों में मतभेद है; हालाँकि, वे निश्चित हैं कि यह अन्य राज्यों के प्रति एक राज्य के व्यवहार से संबंधित है। जॉर्ज मॉडल्स्की के अनुसार, षविदेश नीति समुदायों द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने और अंतरराष्ट्रीय वातावरण में अपनी गतिविधियों को समायोजित करने के लिए विकसित गतिविधियों की प्रणाली है विदेश नीति को उन तरीकों पर प्रकाश डालना चाहिए जिनमें राज्य बदलने का प्रयास करते हैं। , और अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने में सफल होते हैं।ष (जॉर्ज मॉडल्स्की, ए थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, (लंदन, 1962) पीपी.6–7) प्रत्येक राज्य का व्यवहार हर दूसरे राज्य के व्यवहार को किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिक या कम तीव्रता के साथ, अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। प्रतिकूल रूप

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

से। विदेश नीति का कार्य प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और अन्य राज्यों के कार्यों के अनुकूल प्रभावों को अधिकतम करने का प्रयास करना है। विदेश नीति का उद्देश्य न केवल बदलना है बल्कि अन्य राज्यों के व्यवहार को उनके अनुकूल कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करके विनियमित करना भी है। उदाहरण के लिए, कश्मीर पर ग्रेट ब्रिटेन का रुख शीत युद्ध की अवधि के दौरान अस्पष्ट था। इधर, भारतीय विदेश नीति ने भारत के पक्ष में ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति को बदलने का प्रयास किया। दूसरी ओर, तत्कालीन सोवियत संघ ने कई वर्षों तक कश्मीर के प्रश्न पर भारत का समर्थन किया। इस मामले में, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य यूएसएसआर की अनुकूल स्थिति की निरंतरता सुनिश्चित करना था।

विदेश नीति एक जटिल और गतिशील राजनीतिक अंतःक्रिया है जो एक राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अन्य राज्यों और संस्थाओं के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में शामिल हो जाता है। जैसा कि जोसेफ फ्रेंकल कहते हैं, षविदेश नीति में निर्णय और कार्य होते हैं, जिसमें एक राज्य और अन्य के बीच कुछ सराहनीय सीमा तक संबंध शामिल होते हैं।ष (जोसेफ फ्रैन्केल, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, पृ.1) इसका तात्पर्य है कि विदेश नीति में राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने वाली ताकतों और देश की सीमाओं के बाहर मौजूद ताकतों के लिए काम करने वाले बलों द्वारा कार्रवाई शामिल है। यह अन्य राज्यों द्वारा कानून बनाने की शक्ति के प्रयोग के साथ–साथ अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर गैर–राज्य अभिनेताओं के कार्यों को प्रभावित करने के लिए राज्य द्वारा नियोजित उपकरणों का एक सेट है। इसमें विचारों के एक समूह का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है जो अपने हितों की रक्षा और बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों के साथ बातचीत करते हुए राज्य के अभिनेताओं के व्यवहार को नियंत्रित करता है।

राष्ट्रीय हित और विदेश नीति

आधुनिक समय में, विदेश नीति की निरंतरता और निरंतरता के लिए, इसे घरेलू दर्शकों, यानी देश के नागरिकों के साथ वैधता हासिल करनी होगी। यह देश की विदेश नीति के माध्यम से कथित राष्ट्रीय हित के अथक प्रयास द्वारा प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय हित किसी देश के नागरिकों द्वारा नीति निर्माताओं को बताई गई जरूरतें, लक्ष्य या इच्छाएं हैं। इस तरह के लक्ष्य, जरूरतें और इच्छाएं अलग–अलग राज्यों और समय–समय पर काफी भिन्न होती हैं। राज्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है, जो सामान्य और सतत लक्ष्य हैं। राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंधों में राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने या उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय हित को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया गया है जैसे कि आक्रामकता के खिलाफ रक्षा, उच्च जीवन स्तर विकसित करना या संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सही जगह की तलाश करना। चार्ल्स लेरचे और अब्दुल सईद ने राष्ट्रीय हित को परिभाषित करते हुए कहा, ष्सामान्य दीर्घकालिक और सतत उद्देश्य जिसे राज्य, राष्ट्र और सरकार सभी स्वयं को सेवा के रूप में देखते हैं।ष (चार्ल्स ओ. लेर्चे जूनियर और अब्दुल ए सैद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणाएं, (एंगेलवुड क्लिफ्स, 1963), पृष्ठ 6)

राष्ट्रीय हितों को दो श्रेणियों में बांटा गया है; महत्वपूर्ण या मुख्य हित और महत्वपूर्ण या गौण हितों से कम। काउंटी की विदेश नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हित सबसे महत्वपूर्ण हैं। राज्य महत्वपूर्ण हितों के साथ

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और अपने बचाव में युद्ध छेड़ने के लिए निश्चित है। भारत का कहना है कि कश्मीर उसके लिए महत्वपूर्ण हित का मुद्दा है। चीन घोषित करता है कि ताइवान और तिब्बत उसके लिए महत्वपूर्ण हित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को गिराने को उसके लिए महत्वपूर्ण हित का मुद्दा माना। किसी राज्य के महत्वपूर्ण हित इतने बुनियादी होते हैं कि वे अपनी विदेश नीति के एजेंडे में लगभग स्थायी स्थान प्राप्त कर लेते हैं और अक्सर जनता के बीच भावनात्मक अपील पैदा करते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत की विदेश नीति के निर्माण, निर्धारण तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया का विश्लेषण करना जिससे यह समझा जा सके कि विदेश नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में किन–किन व्यक्तियों एवं संस्थाओं की क्या भूमिका होती है।

2. विदेश नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में किन परिस्थितियों में क्या–क्या निर्णय लिए गये? और उनके पिछे क्या कारक थे

विदेश नीति निर्माण में प्रभावशाली कारक

आतंरिक कारक

1. आकारः राज्य का क्षेत्रीय आकार उसकी विदेश नीति को इस अर्थ में प्रभावित करता है कि राज्य जितना बड़ा आकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निभा सकता है। विश्व राजनीति में महान शक्ति का दर्जा हासिल करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को इसके आकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो दुनिया का 7 वां सबसे बड़ा संप्रभु राज्य है। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के महत्व के प्रमुख कारकों में से एक उनका विशाल आकार है। दूसरी ओर, छोटे देशों को आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन से बड़ी भूमिका निभाने के अवसर नहीं मिलते हैं। एशिया–प्रशांत क्षेत्र और अफ्रीका महाद्वीप के छोटे द्वीपीय देश विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। बड़ा आकार किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाता है। भारत विश्व राजनीति में भू–राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विशाल आकार इसे दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशियाई देशों और चीन के अंतर–जंक्शन पर रखता है। भारत की विशाल जनसंख्या को यदि मानव संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो यह उसकी विदेश नीति को भी बल प्रदान करता है। दुनिया का कोई भी महत्वपूर्ण देश इतने विशाल आकार के लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकता और दूसरी ओर भारत को अपनी जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार, राज्य की विदेश नीति के निर्धारण में क्षेत्रीय आकार, भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

2. भूगोलः एक राज्य की जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, जलमार्गों तक पहुंच, खनिज संसाधनों के भंडार, फसलों की विविधता, पीने के पानी की उपलब्धता आदि इसकी विदेश नीति को प्रभावित और प्रभावित करते हैं। इन कारकों की पर्याप्तता राज्य को आत्मनिर्भर बनाती है, और इस प्रकार, यह अन्य राज्यों के साथ संबंधों में मुखर हो सकती है। यह देखा गया है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में और महाशक्तियों से काफी दूरी पर, गर्म बंदरगाहों तक पहुंच वाले देशों की तुलना में भूमि–बंद देश, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश और सीमावर्ती महाशक्तियां अन्य राज्यों पर अधिक निर्भर हैं। स्वतंत्रता के बाद, भारत को किसी भी महाशक्ति ब्लॉक में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था और वह गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति बना सकता था क्योंकि उसके पास अन्य देशों के साथ व्यापार करने के एक से अधिक तरीके थे, उसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करने का विश्वास था और कृषि का विकास, और यह तत्कालीन महाशक्तियों, यानी यूएस और यूएसएसआर से भौगोलिक दूरी पर था।

3. इतिहास और संस्कृतिः किसी राज्य के ऐतिहासिक अनुभव और सांस्कृतिक परंपराएं उसकी विदेश नीति पर प्रभाव डालती हैं। आम तौर पर, एकीकृत संस्कृति और सामान्य इतिहास वाले राज्य को प्रभावी और सुसंगत विदेश नीति तैयार करना आसान लगता है। ऐसे मामले में, ऐतिहासिक घटनाओं के समान अनुभव और आम धारणा साझा करने वाले अधिकांश लोग राज्य की विदेश नीति का समर्थन करते हैं। दूसरी ओर, भिन्न–भिन्न संस्कृतियों और अपने विभिन्न भागों में विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों वाले देश के लिए एक साथ विदेश नीति तैयार करना कठिन होता है। भारतीय समाज में एक समान उपनिवेशवाद–विरोधी विरासत और शांति और सहयोग की गहरी संस्कृति के बिना, सरकार के लिए स्वतंत्रता के बाद के युग में देश की विदेश नीति तैयार करना संभव नहीं था। फिर भी, हाल ही में, भारत सरकार परमाणुकरण, इज़राइल के साथ संबंधों को मजबूत करने, पाकिस्तान को उलझाने, श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार आदि जैसे मुद्दों पर अपनी विदेश नीति में दुविधा का सामना कर रही है। यह वास्तव में नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत अपनी विदेश नीति पर देश में एकमतता पैदा करेगा; विशालता, विविधता, विभिन्न क्षेत्रों की पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक निकटता और सीमाओं के पार वंश को देखते हुए।

4. आर्थिक विकासः आर्थिक विकास का स्तर राज्य की विदेश नीति को एक से अधिक तरीकों से प्रभावित करता है। उन्नत उद्योगपति देश विश्व राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और इस तरह की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीतियां बनाते हैं। इन देशों के पास एक ओर सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने के लिए और सहायता और ऋण के रूप में अन्य राज्यों पर मौद्रिक लाभ फैलाने के लिए उनके निपटान में बड़े संसाधन हैं। वे अपने उत्पादों, कच्चे और प्राकृतिक संसाधनों के साथ–साथ कुशल और अकुशल श्रमिकों तक पहुंच के लिए नए बाजारों की निरंतर खोज में रहते हैं। यह उन पर अन्य राज्यों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध विकसित करने और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक बनाता है। विकासशील देश भी, व्यापार और तकनीकी सफलताओं के लाभ प्राप्त करने के लिए उनके सूट का पालन करते हैं। हालाँकि, विकासशील देश विकासात्मक ऋण, प्रौद्योगिकियों के आयात और यहाँ तक कि खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

बहुत हद तक उन्नत उद्योगपति देशों पर निर्भर रहते हैं। तदनुसार, उसे अपनी विदेश नीति को समायोजित करना होगा। इसी तरह गरीब या कम से कम विकसित देश सहायता, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों और उच्च शिक्षा तक पहुंच आदि के रूप में अमीर देशों से अधिकतम समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी विदेश नीति को उन्मुख करते हैं। हाल के वर्षों में, हमने देखा है कि जर्मनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है यूएनएससी का स्थायी सदस्य न होने के बावजूद यूरोप की राजनीति में भूमिका और एक गैर–परमाणु राज्य होने के नाते। जर्मनी का बढ़ा हुआ भार पूरी तरह से उसके आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। विश्व मंच पर चीन और भारत के उभरने की बातें हाल के वर्षों में उनके आर्थिक पुनरुत्थान पर आधारित हैं। इसके विपरीत, शीत युद्ध के बाद की अवधि में, रूस का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के बाद उसकी आर्थिक शक्ति कम हो गई थी। वास्तव में, यूएसएसआर के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट ब्लॉक के पतन के प्रमुख कारणों में से एक को स्थिर आर्थिक कहा गया था। उन देशों में कई वर्षों से विद्यमान स्थितियाँ।

विदेश नीति निर्माण में संस्थान

विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया विदेश नीति के निर्माण के साथ–साथ निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जे. बंद्योपाध्याय के अनुसार, ष्एक राजनीतिक दल की तर्कसंगतता या अन्यथा स्पष्ट जनमत की प्रकृति और सीमा और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके, विदेश नीति से संबंधित राजनीतिक दलों की संस्थाओं, दबाव समूहों, संसद, विदेश पर निर्भर करती है। कार्यालय, विदेश मंत्री और अंत में कैबिनेट। हम विदेश नीति निर्माण में शामिल संस्थाओं को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं; अनौपचारिक संस्थान और औपचारिक संस्थान। पहले समूह में देश में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग, व्यापक जनमत और दबाव समूह आदि शामिल हैं। औपचारिक संस्थानों में कैबिनेट, संसद, राजनीतिक दल आदि शामिल हैं।

शासक अभिजात वर्गरू शासक अभिजात वर्ग विदेश नीति के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घरेलू और विदेशी परिवेश के बारे में उनकी धारणा और उसमें बनी चुनौतियों का देश के बाहरी संबंधों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह सर्वविदित है कि भारत की विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू के विश्व दृष्टिकोण और संपूर्ण मानव के लिए शांति और समानता के उनके जुनून का परिणाम थी। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद लगभग दो दशकों तक विदेशी मामलों पर नेहरू के विचारों को चुनौती नहीं दी गई, उन्होंने स्वयं कृष्ण मेनन, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉ राधा कृष्णन, केएम पन्निकर, स्वर्ण सिंह आदि जैसे लोगों की बुद्धिमान परिषद की मांग की। प्रारंभिक वर्षों में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की नींव रखने में कुलीन वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। आने वाले वर्षों में, कुछ और विद्वान राजनेता/नौकरशाह इस क्लब में शामिल हुए, उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी, टी.एन. कौल, डी.पी. धर, पी. एन. हक्सर, राजीव गांधी, जे.एन. दीक्षित, ब्रजेश मिश्रा, हामिद अंसारी, आई.के. गुजराल, जसवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह।

जनमतरू भारत जैसे लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश में, संप्रभुता लोगों के पास है। इसलिए, सरकार की सभी नीतियों में, चाहे घरेलू हो या बाहरी मामलों से संबंधित, लोगों की राय और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलनी

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

चाहिए। हालाँकि, भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ गरीबी और निरक्षरता व्यापक है, आम लोग आंतरिक नीतियों में अपने हितों और मांगों की तुलना में देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय ही देश की विदेश नीति में रुचि दिखाते हैं। उच्च स्तर की निरक्षरता, संचार के साधनों की कमी के साथ, लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति निर्माण के बारे में शिक्षित होने में एक बड़ी बाधा साबित हुई। इस प्रकार, देश की विदेश नीति में लोगों की भागीदारी उनके हितों और जरूरतों के कारण ही सीमित है। जब नस्लवाद, साम्राज्यवाद, आतंकवाद और युद्ध जैसे मुद्दों पर स्टैंड लेने की बात आती है तो विदेश नीति में लोगों की इतनी सीमित रुचि के बावजूद, उनका नैतिक दृष्टिकोण और घरेलू राजनीति के सिद्धांत उनकी पसंद में परिलक्षित होते हैं।

भारत की विदेश नीति का विकास

20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, भारत ब्रिटिश शासन के अधीन एक अर्ध–अंतर्राष्ट्रीय इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटेन की सरकार ने युद्ध के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा और विदेशी मामलों से संबंधित मामलों पर भारत और अन्य प्रभुत्वों के साथ नियमित परामर्श करने का एक बिंदु बनाया। चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने विश्व युद्ध के अंत में स्व–शासन के बारे में ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं करने के लिए विश्वासघात महसूस किया, उन्हें शांत करने के लिए, ब्रिटेन ने 1917–18 में युद्ध सम्मेलनों में भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत की आधिकारिक भागीदारी शुरू हुई। इस प्रकार, भारत पेरिस शांति सम्मेलन का पक्षकार था और वर्साय की संधि का हस्ताक्षरकर्ता था जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था। भारत को युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ के मूल सदस्य के रूप में भी स्वीकार किया गया था। इसी तरह, भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का सदस्य बन गया। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत की भागीदारी प्रतीकात्मक नहीं थी लेकिन यह पर्याप्त थी। भारत ने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का मसौदा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई, उदाहरण के लिए, अफीम कन्वेंशन, महिलाओं और बच्चों के यातायात पर कन्वेंशन, गुलामी कन्वेंशन, आदि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का एक पक्ष बन गया और एक मूल हस्ताक्षरकर्ता बन गया। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यों के कई अधिराज्यों में भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों के मुद्दों को भी उठाया। भारत ने स्वतंत्रता पूर्व काल में कई देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य में व्यापार प्रथाओं के साथ घनिष्ठ रूप से उलझा रहा। 1931 में, भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे को तरजीही टैरिफ दरें प्रदान करने के लिए ओटावा में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार, भारत ने अपने स्वतंत्रता–पूर्व दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया, जो विश्व के अधिकांश देशों के साथ शीघ्रता से संबंध स्थापित करने में मददगार साबित हुआ।

ळ

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

21 वीं सदी में विदेश नीति

शीत युद्ध के बाद की स्थिति ने भारतीय विदेश नीति के लिए कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य सभी जिम्मेदार देशों के साथ जुड़ रहा है। हालाँकि, भारतीय विदेश नीति की सहयोग की रूपरेखा इस शीत युद्ध के बाद के युग में कमोबेश एक जैसी है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इसका मूल लक्ष्य देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना और सैन्य गठबंधनों की शर्तों पर विश्व राजनीति को रोकना रहा है। चूँकि विश्व राजनीति में आधिपत्य का विरोध करने और अन्य देशों के खिलाफ सैन्य गठबंधन में प्रवेश करने की भारत की मूल नीति नहीं बदली है, गुटनिरपेक्षता अभी भी इसकी विदेश नीति के लिए प्रासंगिक है। परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रभावी और समयबद्ध उपायों के साथ आने के लिए बिग 5, यानी परमाणु संपन्न राज्यों की विफलता ने भारत को अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुकरण का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया। हालाँकि, भारत एक परमाणु हथियार राज्य के रूप में एक जिम्मेदार भूमिका निभाता है क्योंकि इसने व्यापक और सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण उपायों की मांग के साथ–साथ अपनी श्नो–फर्स्ट यूजश नीति की घोषणा की है। भारत परमाणु दुर्घटना से बचने के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ परमाणु विश्वास निर्माण उपायों की वकालत करता है और इस तरह इन देशों को रचनात्मक बातचीत में शामिल करता है। भारत ने शीत युद्ध के बाद के युग में अपनी विदेश नीति को संतुलित करने और इसे अपनी घरेलू आर्थिक नीति के अनुरूप बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और इज़राइल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसने शक्तिशाली सोवियत संघ के पतन के कारण उत्पन्न रिक्तता को भरने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचने के प्रयासों में भी तेजी लाई है। भारत ने एक–ध्रुवीय विश्व को जारी रखने का विरोध किया है और बहु–ध्रुवीय विश्व के उद्भव को सुनिश्चित करने के लिए रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हाथ मिलाया है। ब्रिक्स और जी–20 नए युग में भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं, भले ही इसने एनएएम और संयुक्त राष्ट्र के समय–परीक्षणित प्लेटफार्मों को नहीं छोड़ा है। भारत संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ–विश्व बैंक संरचनाओं में सुधारों की वकालत कर रहा है ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक और आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रतिबिंबित किया जा सके। भारत सभी देशों के सहयोग से आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग की नई चुनौतियों का समाधान करना चाहता है और इसलिए इस मुद्दे पर सभी अंतरराष्ट्रीय विचार–विमर्शों में पूरे दिल से भाग लेना चाहता है। भारत की विदेश नीति का अंतिम लक्ष्य अपनी स्वतंत्र और संप्रभुता की रक्षा करना, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की तलाश करना और शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना पिछले 60 वर्षों में समान है।

विदेश नीति में परिवर्तन के लिए घरेलू कारक

यह स्पष्ट है कि बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भारत को आर्थिक स्वार्थ की तर्ज पर अपनी विदेश नीति को नए सिरे से तैयार करने में सक्षम बनाया है। फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू प्रेरणाएँ क्या थीं जिन्होंने इस प्रयास को बल दिया। 1980 के दशक के दौरान, एक समाजवादी व्यवस्था की काफी बौद्धिक आलोचना हुई थी, जिसने विकास को व्यंग्यात्मक रूप से हिंदू विकास दर (लगभग 2.5: 3: जीडीपी वार्षिक वृद्धि) के रूप में संदर्भित किया था। सामाजिक–आर्थिक स्पेक्ट्रम के निचले छोर पर समूहों के बढ़ते

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

राजनीतिकरण के साथ, सरकारों के उत्तराधिकार को बेहतर जीवन और अधिक अवसरों के लिए उनकी मांगों का जवाब देने के लिए मजबूर किया गया है। धीमी वृद्धि उन प्रतिक्रियाओं को दो असंतोषजनक विकल्पों तक सीमित कर देती हैरू (1) विशेषाधिकार प्राप्त पदों पर उन समूहों से दूर ले जाना या (2) कुछ नहीं करना। दोनों विकल्पों के परिणामस्वरूप हिंसक सामाजिक विरोध होगा, पहले को विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा और बाद में ऊर्ध्वगामी मोबाइल समूहों द्वारा किया जाएगा। 1990 के दशक की शुरुआत में, ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी और शैक्षिक आरक्षण के प्रस्ताव की वीपी सिंह सरकार की घोषणा ने दिल्ली और अन्य जगहों पर उच्च जाति के छात्रों के बीच विरोध का तूफान खड़ा कर दिया।

समस्याएं और संभावनाएं

भारत को एक विदेश नीति बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो शीत युद्ध के बाद की दुनिया की मांगों को पूरा करती है और भारत में ही नई राजनीतिक वास्तविकताओं को पूरा करती है। यहां यह तर्क दिया जाता है कि निरंतर उच्च जीडीपी विकास दर के लिए घरेलू राजनीतिक और सामाजिक मांगों ने भारत को वैश्वीकरण की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया है, जिसने अपनी विदेश नीति को तेजी से आकार दिया है। ऐसे कई कारक हैं जो इस प्रवृत्ति को धीमा कर सकते हैं, शायद परेशान भी कर सकते हैं। एक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ जारी तनाव है, जो भारत की राजनयिक पूंजी को अवशोषित कर सकता है और साथ ही निवेश को डरा सकता है। पचास साल के अविश्वास को दूर करना मुश्किल है और भारत में गठबंधन सरकारें ऐसे कड़े फैसले लेने को टाल सकती हैं जिन्हें तुष्टिकरण के रूप में निरूपित किया जा रहा है।

जब तक कड़े फैसलों से बचा जाता है, तब तक खतरा बना रहता है कि कश्मीर में एलओसी पर तनाव खुला टकराव तक बढ़ सकता है। यह मई 1999 में हुआ, जब नियंत्रण रेखा पर तनाव फिर से नियंत्रण से बाहर हो जाने की स्थिति में प्रत्येक पक्ष ने अपनी रक्षा मुद्रा में सुधार के लिए एहतियाती कदम उठाए। भारत परमाणु हथियारों पर एक पूर्ण पैमाने पर संघर्ष के खिलाफ एक निवारक के रूप में बहुत अधिक निर्भरता रख सकता है जिसमें परमाणु हथियार शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व उन्हें एक ढाल के रूप में देखता है जिसके पीछे वह उत्तेजक कार्यों में संलग्न हो सकता है जो अन्यथा युद्ध का कारण बन सकता है। दोनों पक्षों ने अभी तक दूसरे पक्ष को अस्वीकार्य व्यवहार के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से लाल रेखाओं पर काम किया है, और 1999 के वसंत और गर्मियों में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच स्व्ब पर लड़ाई प्रत्येक की दूसरे को गलत तरीके से पढ़ने की क्षमता को रेखांकित करती है।

दीर्घकालिक प्रभाव

1990 के दशक की शुरुआत से भारत की विदेश नीति की रणनीति में नवाचारों के परिणामस्वरूप सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों के एक साथ विस्तार, एशिया और हिंद महासागर क्षेत्रों में बढ़ते वजन और महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों की संभावना की सुखद स्थिति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसके आसन्न सापेक्षिक उत्थान को देखते हुए, भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला शक्ति के महत्व पर नया ध्यान समस्याओं के बिना नहीं है। हाल के वर्षों में हाशिए पर रहने के बावजूद, भारत की विदेश

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

नीति से आदर्शवाद और नैतिकता की अनिवार्यता पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। 1991 के बाद से, भारत ष्तर्क की शक्तिष पर अपने पारंपरिक जोर से ष्सत्ता के तर्कष पर एक नए जोर पर चला गया है। अपने शोर–शराबे वाले लोकतंत्र को देखते हुए, भारत विशुद्ध रूप से सत्ता के तर्क पर विदेश नीति की पहल के लिए घरेलू राजनीतिक समर्थन का निर्माण नहीं कर सकता है। इसे विश्व स्तर पर अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए मूल्यों और मानदंडों के एक सेट की आवश्यकता बनी रहेगी। परिणामस्वरूप भारत की विदेश नीति की रणनीति में ष्शक्ति और सिद्धांतष के बीच तनाव एक स्थायी बना रहेगा।

उपसंहार

भारतीय विदेश नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से संरचित प्रतीत होती है (1) देशों के साथ घनिष्ठ संबंध और बहुपक्षीय संघ जो आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं; और (2) अपनी विदेश नीति को एक प्रमुख एशियाई शक्ति के रूप में संचालित करने में सक्षम होना, न कि केवल एक क्षेत्रीय दक्षिण एशिया राज्य के रूप में। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत को अन्य देशों को यह समझाने की आवश्यकता है कि वह उनसे अपने गुणों के आधार पर निपटेगा न कि भारत–पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में। चूंकि भारत विश्व में भविष्य में शक्ति संतुलन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरता है, इसलिए कम से कम विशिष्ट मुद्दों पर एक या दूसरी महान शक्तियों के पक्ष में चुनाव करने के लिए दबाव डाला जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में महान शक्ति टकराव की अनुपस्थिति ने भारत को ष्गुटनिरपेक्षष के नारे को ष्स्वतंत्रष विदेश नीति में परिवर्तित करने की विलासिता की अनुमति दी है। लेकिन अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस और जापान के बीच संभावित नई प्रतिद्वंद्विता के बीच, नई दिल्ली को अक्सर भयावह राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले दशकों में भारत से अपने तत्काल और विस्तारित पड़ोस में व्यवस्था और स्थिरता में योगदान करने की मांग में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। यह बदले में भारत को विभिन्न क्षेत्रों में महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता और छोटे देशों के आंतरिक संघर्षों में और गहरा कर देगा।

संदर्भ

[1] बंद्योपाध्याय, जे, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2003, नई दिल्ली

[2] ब्रेचर, मियाचेल, इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्सरू कृष्णा मेनन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ओयूपी, 1968, लंदन

[3] चंद्रा, बिपिन और अन्य, स्वतंत्रता के बाद से भारत, पेंगुइन बुक्स, 2007, नई दिल्ली

[4] दीक्षित, जे.एन., माई साउथ ब्लॉक इयर्सरू एक विदेश सचिव के संस्मरण, डब्ल्यूबीएसपीडी, 1996, नई दिल्ली

[5] जैन, पीसी, भारत की विदेश नीति के आर्थिक निर्धारकरू नेहरू इयर्स, विस्तार प्रकाशन, 2012, नई दिल्ली

ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

[6] नेहरू, जवाहरलाल, भारत की विदेश नीति, प्रकाशन विभाग, 1962, नई दिल्ली

[7] अमिताभ मट्टू, इमेजिनिंग चाइना, कांति बाजपेयी और अमिताभ मट्टू ने द पीकॉक एंड द ड्रैगनरू इंडिया–चाइना रिलेशंस इन द 21 सेंचुरी, हर–अनद प्रकाशन 2000, का संपादन किया।

[8] जे. मोहन मलिक, ष्21 वीं सदी में भारत–चीन संबंधरू निरंतर प्रतिद्वंद्विताष्, ब्रह्म चेलानी संपादित, न्यू मिलेनियम में भारत के भविष्य को सुरक्षित करना, ओरिएंट लॉन्गमैन, 1999,

[9] फ्रैंकलिन और हार्डिंग, भारत–चीन संबंधरू नदी और सगाई (नई दिल्लीरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004)

[10] डिटमर एल, दक्षिण एशिया की सुरक्षा दुविधारू भारत, पाकिस्तान और चीन (न्यूयॉर्करू एम ई शार्प, 2005)

[11] रजत कांता रे, ष्भारतीय समाज और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना, 1765–1818ष् लुइस में, विलियम रोजर एट अल। (संस्करण), द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायररू द अठारहवीं सेंचुरी, ऑक्सफोर्डरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001, पी। 514.

[12] संजय बारू, ष्भारतीय आर्थिक विकास में निर्भरता के लिए आत्मनिर्भरता,ष् सामाजिक वैज्ञानिक, वॉल्यूम। 11, नंबर 11 (नवंबर 1983), पीपी। 34–46।

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by mean if any person having copyright issue or patent or anything other wise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me isnot correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents

ISSN: 2320-3714
Volume 3 Issue 3
September 2022
Impact Factor: 11.9
Subject Humanities

(Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed I website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me

Sachin Sharma
Dr. Shweta Rai

******